सफलता की कहानी...

समग्र सहकारी विकास परियोजना जयपुर का क्रियान्वयन

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वित्तीय सहयोग से जयपुर जिले की 25 करोड़ 57 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई। इसमें एनसीडीसी द्वारा 23 करोड़ 52 लाख रुपए व 2 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। जयपुर जिले की पांच वर्षीय योजना 30 सितंबर, 2016 को पूरी होगी। इस परियोजना में एनसीडीसी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशि में से 18 करोड़ 27 लाख रुपए ऋण के रुप में व 5 करोड़ 24 लाख रुपए से अधिक की राशि अनुदान के रुप में सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध होगी। जयपुर जिले की समग्र सहकारी विकास परियोजना का योजनाबद्ध क्रियान्वयन का परिणाम यह रहा है कि परियोजना के लिए प्राप्त राशि 20 करोड़ 52 लाख रुपए में से 20 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की राशि सहकारी संस्थाओं को जारी की जा चुकी है।

परियोजना का तय समय सीमा में योजनाबद्ध क्रियान्वयन के प्रयासों का परिणाम है कि तीन वर्ष पूरे होते होते जिले की सहकारी संस्थाओं को ठोस वित्तीय आधार व आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हो सकी है। महाप्रबंधक श्री भारत भूषण ने परियोजना के योजनाबद्ध क्रियान्वयन व प्रभावी मोनेटरिंग पर जोर दिया जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

परियोजना का क्रियान्वयन

- परियोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए एनसीडीसी के स्वीकृति पत्र दि 23.08.11 का गहन अध्ययन करते हुए यह पाया गया कि परियोजना लागत 25 करोड़ 57 लाख रुपए में से सहकारी संस्थाओं को सहायता हेतु 84 प्रतिशत राशि 21 करोड़ 47 लाख रुपए की लगभग 50 प्रतिशत राशि (10 करोड़ 55 लाख रु) जयपुर जिले की 261 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए हैं।
- परियोजना स्वीकृति पत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य सभी सहकारी - यथा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, सीसीबी, पीएलडीबी एवं 7 अन्य सहकारी संस्थाओं के लिए मय उद्देश्य व प्रयोजन के सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का स्पष्ट प्रावधान किया गया।
- ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रावधानों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि समितियों का दौरा कर वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन कर प्रयोजन वार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया। इससे समितियों को वास्तविक लाभ प्राप्त हो सका। इसके लिए जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक की सभी 21 शाखाओं के ऋण पर्यवेक्षकों एवं पैक्स् व्यवस्थापकों से चर्चा, समितियों का विजिट कर संचालक मण्डल के सदस्यों से चर्चा करके वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर राशि जारी करने का निर्णय किया गया।
- 140 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम मरम्मत सहायता हेतु चिन्हित किया गया।
- 35 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नए गोदाम निर्माण सहायता हेतु चिन्हित किया गया।

- 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के क्षेत्र में उपभोक्ता/मिनी बैंक व्यवसाय वृद्धि की प्रबल संभावनाएं को देखते हुए दुकान/मिनी बैंक भवन निर्माण सहायता हेतु चिन्हित किया गया।
- 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का तिजोरी, फर्नीचर, बैंकिंग काउण्टर की आवश्यकता को देखते हुए का चयन किया गया।

News @ पेज 6

ICDP (Integrated Cooperative Development Project) Jaipur

Shahpura KVSS-New Godown Construction Work (250 M.T.)-I

Brief Detail of Work

Date of Sanction	[illegible]	
Amount of Total Assistance	Loan	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	Subsidy	[illegible]
	Total	[illegible]
Release of Installments	I	[illegible]
	II	[illegible]
	III	[illegible]
Completion of Work	[illegible]	
Completion Period	[illegible]	

जयपुर परियोजना अन्तर्गत दि 30.09.14 तक की सैक्टरवार प्रगति निम्नानुसार रही है :-

(राशि लाख रू में)

सैक्टर विवरण	प्रावधान (13-14 तक)	13-14 तक के प्रावधान के विरूद्ध			
		स्वीकृत		व्यय/रिलीज	
		राशि	प्रावधान पर प्रतिशत	राशि	स्वीकृत पर प्रतिशत
ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सहायता	889.00	887.49	99	855.76	96
क्रय विक्रय सहकारी समितियों को सहायता	376.00	406.00	108	369.10	91
अन्य सहकारी संस्थाओं (सह मुद्रणालय, म भण्डार एवं महिला सह समितियों) को सहायता	67.00	66.00	98	66.00	100
बैंकिंग सह संस्थाओं (जयपुर सीसीबी एवं जयपुर पीएलडीबी) को सहायता	483.10	483.10	100	289.76	60
पीआईटी व्यय - प्रशिक्षण	26.00	26.34	101	26.34	100
पीआईटी व्यय - अन्य	211.31	154.81	73	154.81	100
कुल	2,052.41	2,023.74	98	1,761.77	87

परिसंपत्तियों का निर्माण

(अ) भवन निर्माण

- 35 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100-100 एमटी के नए गोदाम निर्माण का निर्णय किया गया। इनमें से 28 समितियों में गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष 7 कोथून, चन्दलाई, साली, पांचूडाला, छोटी डूंगरी, सिनोदिया एवं भामरू ग्राम सेवा सहकारी समितियों में निर्माण कार्य जारी है।
- 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में दुकान/मिनीबैंक भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई , जिसमें से 46 समितियों में कार्य पूर्ण हो चुका है और अजयराजपुरा, शाहपुरा, मण्डाभीमसिंह एवं बाठापदमपुरा में कार्य जारी हैं।
- 9 विपणन सहकारी समितियों में 15 निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी की गई जिसमें से 9 समितियों में निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 6 सांगानेर में दुकान निर्माण तथा कार्यालय भवन निर्माण, शाहपुरा में एग्रोसर्विस सेन्टर स्थापना, चौमू में गोदाम निर्माण, सांभर में गोदाम निर्माण, जयपुर फल-सब्जी में कार्यालय भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं।

(ब) भवन मरम्मत

- 139 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम मरम्मत कार्यों में से 106 समितियों में मरम्मत का काम पूरा हो चुका है।
- 8 विपणन सहकारी समितियों के स्वीकृत 12 मरम्मत/सुधार कार्यों में से 10 काम पूरे हो चुके हैं। सांगानेर में गोदाम मरम्मत एवं सांभर में कार्यालय सुधार कार्य जारी है। जिन्हें यथाशीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास हैं।

जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण

जयपुर परियोजना अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये तृतीय वर्ष (13-14) तक प्रावधित राशि 26 लाख रू के विपरीत दिनांक 30 सितम्बर, 14 तक 26.34 लाख रू (101 प्रतिशत) राशि व्यय हुई हैं :-

- ग्राम सेवा सहकारी समिति की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के 116 प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं साधारण सदस्यों के 55 शिविरों का आयोजन किया गया।
- राईसेम द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 409 व्यवस्थापकों एवं सहायक कार्मिकों के 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया।
- टोपिक गुडगॉव के माध्यम् से आयोजित 4 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 8 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- जिले के 23 सहकार कर्मियों का चण्डीगढ़, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, मनाली विजिट (स्टडी टूयूर) आयोजित कराया गया।
- जयपुर परियोजना द्वारा स्वीकृतियों से शेष राशि के व्यय की भी कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्ययोजना के अनुसार-
  - केन्द्रीय सहकारी बैंक जयपुर में एक करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से मुख्यालय व शाखा भवन निर्माण, फर्नीचर फिक्चर्स, एटीएम स्थापना की जाएगी।
  - एक प्राथमिक महिला सहकारी समिति को वित्तीय सहयोग का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

समग्र सहकारी विकास परियोजना जयपुर के महाप्रबंधक श्री भारत भूषण के योजनाबद्ध क्रियान्वयन के प्रयासों का ही परिणाम है कि जिले की सहकारी समितियों में आधारभूत सुविधाओं, गुणवत्तायुक्त परिसंपत्तियों का निर्माण और योजना प्रावधानों का समयबद्ध उपयोग संभव हो पाया है। परियोजना के क्रियान्वयन का लाभ भी क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जिले की सहकारी संस्थाओं की सक्षमता, आधारभूत सुविधाओं से जिले के काश्तकारों और आमनागरिकों को लाभ मिलने लगा है।

61 वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह-2014 के सहकारिताएं एवं समर्थ विधान दिवस के अवसर पर श्री एन. के. मौर्य, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड बीकानेर, सहकार कर्मियों को जानकारी देते हुए।